being a net importer of aluminium metal. India becomes a surplus producer of aluminium by 1988-89.

गंगा के दियारा क्षेत्र में भूमि की सिंचाई

*177. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा के दियारा क्षेत्र में भूमि की सिंचाई के वास्ते सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गयी है ;

(ख) उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में गंगा के दियारा खादर क्षेत्र के लिए बनायी गयी बृहद, मध्यम और लघु योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस विशाल क्षेत्र के विकास के लिए अलग से कोई उपयोगी योजना बनायी गयी है ; यदि हां, तो बिहार के लिए बनायी गयी ऐसी योजना का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) से (ग) राज्य सरकारों से दियारा क्षेत्रों के लिए कोई बृहद और मध्यम योजनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं तथा सातवीं योजना में निधियों का विशिष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया गया है । लघु योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा सीधे कार्यान्वित की जाती है और उनके बारे में ब्यौरे केन्द्र द्वारा नहीं रखे जाते हैं ।

Revision of price of land by the D.D.A. for service personnel

*178. DR. RATNAKAR PANDEY:
SHRI MAHENDRA PRASAD:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the D.D.A. has, through a recent order, revised the price of land for service personnel; and

(b) if so, what are the reasons for revising the price of land and what is the extent of the rise in the land prices?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRIMATI MOHSINA KIDWAI): (a) and (b) In respect of land allotted to Cooperative Group Housing Societies measuring less than two acres each, deficiency charges were being levied at the predetermined rate of Rs. 54/- per Sq. Mtr., on an ad-hoc basis, for the 2 per cent area not provided by the Society for service personnel housing. In July 1986, a view was taken by the DDA that these charges should be levied at market rates, since it was felt that the terms and conditions of allotment had been violated. However on reconsideration, a decision to revert to the predetermined rate has since been taken.

झांसी नगर के लिए पेयजल

*179. **डा० गोविन्द दास रिछारिया** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के झांसी नगर में पेयजल के संकट को दूर करने के लिए माताटीला बांध से एक पृथक लाइन डालने की किसी योजना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पेयजल की वर्तमान कमी को ध्यान में रखते हुए इस योजना पर कब तक कार्य आरम्भ कर दिये जाने की आशा है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए झांसी जलपूर्ति पुनःसंगठन योजना के संबंध में एक प्रस्ताव भेजा है ।